

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र० क० 880-दो/2012 विरुद्ध आदेश दिनांक 12-01-12
पारित अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर प्रकरण क्रमांक
167/अ-67/10-11 अपील.

राजेन्द्रसिंह पुत्र तिलकसिंह
निवासी ग्राम अटाकर्नेलगढ़,
तह० मालथौन, जिला सागर

— आवेदक

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर,
जिला सागर, म० प्र०

— अनावेदक

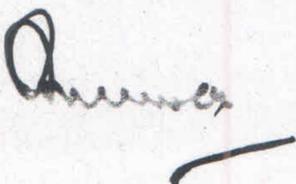
श्री के०के० द्विवेदी, अभिभाषक - आवेदक
श्री बी०एन० त्यागी, पैनल अभिभाषक- अनावेदक शासन

आदेश

(आज दिनांक 25.8.2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के अपील प्रकरण क्रमांक 167/अ-67/10-11 में पारित आदेश दिनांक 12-01-12 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

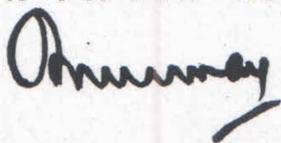
2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अनुविभागीय अधिकारी, खुरई द्वारा गठित दल द्वारा जाँच के दौरान पाया गया कि भूमि खसरा नं० 131 रकबा 1.85 हे. से लगभग 16 टक पत्थर का अवैध पत्थर आवेदक राजेन्द्रसिंह पिता तिलकसिंह द्वारा निकला गया। अतः संहिता की धारा 247(7) के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर आवेदक को कारण बताओ सूचनापत्र दिया गया। आवश्यक कार्यवाही के पश्चात अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश



दिनांक 29-11-2010 द्वारा 16 टक पत्थर का बाजार मूल्य 1.60 लाख होने से आवेदक पर बाजार मूल्य से दुगना अर्थात् 3.20 लाख रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया। इस आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील में कलेक्टर जिला सागर ने अपने आदेश दिनांक 29-09-11 में यह निष्कर्ष निकाला कि गठित संयुक्त दल द्वारा स्थल निरीक्षण तथा सर्वे दल के सदस्य श्री मरावी के कथनों से स्पष्ट है कि राजेन्द्रसिंह ने शासकीय भूमि खसरा नं0 131 से बिना पूर्व अनुमति के अवैध रूप से 16 टक पत्थर निकाला गया। खनिज का तत्समय बाजार मूल्य 1.60 लाख होने से आरोपित शास्ति को सही होना माना और अपील खारिज की। द्वितीय अपील अपर आयुक्त द्वारा खारिज की गयी है। अतः आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की है।

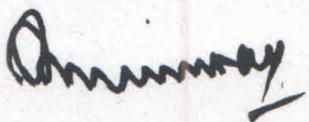
3/ मैने अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदक के अभिभाषक ने लिखित बहस में यह तर्क प्रस्तुत किया है कि धारा 247 में बनाये गये आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत जाकर विचारण न्यायालय ने आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक को सुनवायी एवं साक्ष्य का विधिवत अवसर प्रदान किये बिना आदेश पारित किया गया है। जॉच कमेटी द्वारा प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन परे स्वतंत्र साक्षियों की साक्ष्य लिये बिना आदेश पारित किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि धारा 247(7) का कारण बताओ सूचनापत्र कलेक्टर द्वारा दिया जाना चाहिये था, परन्तु उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो अवैधानिक है। आवेदक को शासकीय साक्ष्य का प्रतिपरीक्षण का अवसर नहीं दिया गया। मौके पर किसी प्रकार का कोई पत्थर जप्त नहीं किया गया। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया है।

4/ अनावेदक के पैनल अभिभाषक का तर्क है कि आवेदक द्वारा बिना अनुमति के शासकीय भूमि से अवैध पत्थर का उत्खनन किया। शासन की ओर से विधिवत साक्ष्य लेने के पश्चात अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश पारित



किया है। उनका तर्क है कि आवेदक को विधिवत कारण बताओ सूचनापत्र अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिया गया जिसका जबाव भी आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आवेदक का बयान भी विचारण न्यायालय ने लिपिबद्ध किया है जिसमें उसने उत्खनन मकान बनाने के लिये करना स्वीकार किया है। अनुविभागीय अधिकारी को संहिता की धारा 247(7) के अन्तर्गत अधिकारिता शासन द्वारा प्रदत्त की गयी है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ अनुविभागीय अधिकारी की आदेश पत्रिकाओं से स्पष्ट है कि आवेदक राजेन्द्रसिंह ने दिनांक 31-3-05 को कारण बताओ नोटिस का जबाव प्रस्तुत किया और उसकी उपस्थिति में हल्का पटवारी एवं ग्राम कोटवार के कथन अंकित किये गये। शेष साक्ष्य हेतु अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 4-4-05 नियत की। दिनांक 4-4-2005 को अनावेदक राजेन्द्रसिंह तथा नायब तहसीलदार, मालथौन एवं राजस्व निरीक्षक, मालथौन उपस्थित हुए और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा श्री एस0के0 जैन, नायब तहसीलदार एवं श्री टी. पी. श्रीवास्तव, राजस्व निरीक्षक के कथन अंकित किये तथा शेष साक्षियों को नोटिस जारी करने के आदेश देते हुए प्रकरण 11-04-05 को नियत किया। नियत दिनांक 11-04-05 को आवेदक राजेन्द्रसिंह अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में उपस्थित था और उसकी उपस्थिति में पुलिस चौकी प्रभारी श्री पी.डी. शुक्ला, डिप्टी रेंजर श्री बी. एस. मरावी तथा खनिज अधिकारी श्री विकास सोनी के कथन अंकित किये गये और प्रकरण अनावेदक/आवेदक की साक्ष्य हेतु 15-4-05 को नियत किया। दिनांक 15-4-05 को प्रकरण पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त रहने से बढ़ाया गया और प्रकरण में आगामी तिथि 7-5-05 नियत की। तत्पश्चात आवेदक अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनेकों बार सूचनापत्र भेजने के पश्चात दिनांक 22-6-07 को अनावेदक/आवेदक को जमानती वारन्ट से तलब करने के आदेश दिये और प्रकरण 9-7-07 को नियत किया। आवेदक दिनांक 9-7-07, 23-7-07 को अनुविभागीय अधिकारी

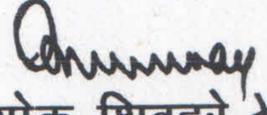


के न्यायालय में उपस्थित हुआ, किन्तु उसके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी और तत्पश्चात पुनः अनुपस्थित रहा। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को पुनः सूचनापत्र जारी कर आहूत किया गया। दिनांक 28-9-08 को आवेदक अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में उपस्थित हुआ और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा शासन की ओर से पटवारी एवं अनावेदक/आवेदक राजेन्द्रसिंह के कथन अंकित किये तथा अनावेदक/आवेदक के तर्क सुनने के बाद प्रकरण आदेश हेतु नियत किया।

6/ उक्त विवेचना से स्पष्ट है कि शासन की ओर से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक की उपस्थिति में शासन की साक्ष्य लिपिबद्ध की गयी है तथा आवेदक को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिया गया, किन्तु आवेदक द्वारा जबाव एवं अपने स्वयं के कथन के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी और ना ही शासकीय साक्ष्य का प्रतिपरीक्षण किया गया। शासन द्वारा प्रस्तुत की गयी साक्ष्य से शासकीय खसरा नं0 131 से आवेदक द्वारा 16 टक पत्थर का अवैध उत्खनन करना सिद्ध है। आवेदक राजेन्द्रसिंह का बयान अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख पृष्ठ 37 पर उपलब्ध है। राजेन्द्रसिंह ने अपने बयान में स्वयं कहा है कि भूमि खसरा नं0 131 के भाग से मकान बनाने के लिए पत्थर निकाले थे, 5X6 का गड्ढा खोदा था। वर्तमान में कार्य बन्द है। आवेदक द्वारा मकान बनाना साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया गया है। ऐसी दशा में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक द्वारा शासकीय भूमि से अवैध उत्खनन करने से बाजार मूल्य रू. 1.60 लाख की दो गुना राशि रू. 3.20 लाख अर्थदण्ड आरोपित करने में कोई त्रुटि नहीं की है। संहिता की धारा 247 (7) की शक्तियाँ शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को प्रदत्त की गयी है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी कारण बताओ सूचनापत्र क्षेत्राधिकार रहित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा तथ्य के संबंध में समवर्ती निष्कर्ष निकाले हैं जिनमें निगरानी में हस्तक्षेप करने का समुचित आधार नहीं है।



7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी खारिज की जाती है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 12-01-12 तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश यथावत रखे जाते हैं।


(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, म0प्र0